



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 2004/कार्तिक 17, 1926

No. 261]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 2004/KARTIKA 17, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2004

सार्वजनिक सूचना सं. 21/2004—09

सं. 01/94/180/0009/एम 05/पीसी 4.—विदेश व्यापार नीति, 2004—09 के पैराग्राफ 2.4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 2.9.5 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“ प्रत्येक आयातक-निर्यातक कोड धारक (उन्हें छोड़कर जिन्होंने पिछले लाइसेंसिंग वर्ष यानि 1.4.2003 से 31.3.2004 में आयातक निर्यातक कोड प्राप्त कर लिया है) को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में किए गए आयात/निर्यात का ब्यौरा 31 दिसम्बर, तक प्रस्तुत करना होगा। आयातक-निर्यातक कोड धारक वेबसाइट www.nic.in/eximpol के माध्यम से आन लाईन पर सूचना प्रस्तुत करेगा।”

2. आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति की वैधता से संबंधित पैरा 2.12(iii) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

स्पेयर्स, अपवर्तक, उत्प्रेरक और उपभोग्यों हेतु
ईपीसीजी लाइसेंस

ईपीसीजी लाइसेंस की अवधि निर्यात
दायित्व की अवधि के साथ ही समाप्त
होगी।

3. पैरा 5.3.1 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

“ परिशिष्ट 9 के अनुलग्नक 1 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी इंजीनियर (सीईसी) के प्रमाण पत्र के आधार पर, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी ईपीसीजी लाइसेंस जारी करेगा और उसके बाद सीईसी की प्रति के साथ ईपीसीजी लाइसेंस की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा ।”

4. पैरा 2.13.1 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा

“ तथापि, मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमतियों और स्टॉक ओर विक्रय लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पुनः वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी जब तक कि सीमाशुल्क प्राधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अभिरक्षा में लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमतियों की समाप्ति न हो गई हो ।”

5. पैरा 2.12.2 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“ वैधता की अवधि का अर्थ है लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के अन्तर्गत आने वाले माल का पोतलदान/प्रेषण/आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति की वैधता इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.11क में दिए गए अनुसार आपूर्ति के देश से माल के पोत लदान/प्रेषण की तारीख से निश्चित की जाती है न कि भारतीय पतन पर माल के पहुँचने की तारीख से ।”

6. पैरा 3.2.3 संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

“ गैर सेवा प्रदायकों के मामले में स्तर प्रमाण पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन के साथ “स्तर प्रमाण-पत्र के लिए निर्यात वसूली/मान्य निर्यातों का बैंक प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जैसा कि परिशिष्ट 17-ख में दिया गया है । तथापि, यह शर्त मौजूदा स्तर धारकों पर लागू नहीं होगी जोकि मौजूदा स्तर के पुनःनवीकरण और उन्नयन के लिए आवेदन कर रहे हैं ।”

7. पैरा 5.10 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:-

“ यदि योजना के अन्तर्गत जारी किया गया लाइसेंस, लाइसेंस का जागत बीमा भाड़ा मूल्य 10 प्रतिशत से ज्यादा/कम मूल्य के आयात हेतु उपयोग में लाया गया है, लाइसेंस उस अनुपात में बढ़ा हुआ समझा जाएगा। सीमा शुल्क प्राधिकारी लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना स्वतः ही लाइसेंस मूल्य के 10 प्रतिशत से ज्यादा की वस्तुओं की निकासी की अनुमति दे सकता है”।

ऐसे मामलों में लाइसेंस धारक बाद में किए गए आयात के बढ़ाए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त शुल्क अदा करेगा। निर्यात दायित्व को स्वतः उसी अनुपात में बढ़ा हुआ समझा जाएगा।

8. पैरा 2.20 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे:-

क. निम्नलिखित शब्द क्रम सं. 2 में विनिर्माता निर्यातक शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं-

“(स्वामित्व और भागीदारी फर्मों को छोड़कर)”

ख. नीचे क्रम सं. 8 के नीचे तीसरे उप-पैरा में पहला वाक्य संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“उपर्युक्त 3.4 और 5 श्रेणियों में यदि निर्यातक ने पिछले 3 वर्षों में निर्यात नहीं किया है, तो बचाई गई शुल्क राशि पर 25 प्रतिशत बैंक गारण्टी शर्त की लगाई जाएगी, बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य घरेलू कारोबार के 200 प्रतिशत अथवा पिछले लाइसेंसिंग वर्ष की आपूर्तियों के पोत पर्यन्त निःशुल्क/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 200 प्रतिशत से अधिक न हो, दोनों में जो भी अधिक हो।”

9. पैरा 4.7 को संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्धारित तदर्थ/सियॉन के अनुसार अन्तिम समायोजन के लिए आवेदक द्वारा स्वतः घोषणा और वचनबद्धता के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अग्रिम लाइसेंस भी जारी कर सकता है, जहाँ सियॉन निर्धारित नहीं किए गए हों। तथापि, पशु के सींग, खुर और अन्य अंग अथवा किसी भी मद के लिए जिसके लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार उसे अधिसूचित करे, के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस पैराग्राफ 4.7 के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। परफ्यूम, परफ्यूम यौगिक और विटामिन युक्त विभिन्न पोषक घटकों के निर्यात हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पैरा 4.7 के तहत कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और आवेदक प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4.4.2 के तहत आवेदन कर सकता है। जहाँ जैव प्रौद्योगिकी मदों का निर्यात और/अथवा आयात निहित है उन मामलों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पैरा 4.7 के तहत लाइसेंस जारी किया जा सकता है।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2004

PUBLIC NOTICE No. 21/2004—09

No. 01/94/180/0009/AM05/PC-IV.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-09, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment (s) in the Handbook of Procedures (Vol. I) :—

1. **Para 2.9.5** is amended to read as under-

"Each IEC holder (barring those who have obtained IEC in the preceding licensing year i.e 1.4.2003 to 31.3.2004) shall be required to furnish yearly details of imports/exports made by him in the preceding licensing year by **31st December**. The information shall be furnished online by the IEC holder by accessing the website at www.nic.in/eximpol."

2. **Para 2.12 (iii)** pertaining to the validity of an import licence/ certificate/ permission is amended as under-

EPCG Licence for Spares, Refractories,
Catalyst and Consummables

**Co-terminus with the Export Obligation
Period of the EPCG Licence**

3. **Para 5.3.1** is amended to read as under-

"The Licensing Authority concerned shall, on the basis of the certificate from the Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Annexure I to Appendix 9, issue the EPCG licence and thereafter forward a copy of the EPCG licence along with a copy of the CEC to the concerned Jurisdictional Central Excise Authority."

4. **Para 2.13.1** is amended to read as under-

"However, revalidation of **freely transferable** licence/certificate/permissions and stock and sale licence/certificate/permission shall not be permitted unless the licence/ certificates/ permissions have expired while in custody of the Customs authority/ licencing authority."

5. **Para 2.12.2** is amended to read as under-

"The period of validity means the period for shipment/ dispatch of goods covered under the licence/certificate/ permission. The validity of an import licence/ certificate/ permission is decided with reference to the date of shipment/ dispatch of the goods from the supplying country as given in **Paragraph 9.11 A** of this Handbook and not the date of arrival of the goods at an Indian port."

6. **Para 3.2.3** is amended to read as under-

"The application for grant of status certificate in the case of non service providers mandates the submission of a "Bank Certificate of Export Realisation/ Deemed Exports for Status Certificate" as given in Appendix-17B. However, this provision shall not apply to existing Status Holders who are seeking renewal or upgradation of existing status."

7. **Para 5.10** is amended to read as under-

“If the licence issued under the scheme has actually been utilized for import of a value in excess of 10% of the CIF value of the licence, licence shall be deemed to have been enhanced by that proportion. The Customs shall automatically allow the clearance of goods in excess of 10% of the licence value without endorsement by the licensing authority.

In such cases, the licence holder shall furnish additional fee to cover the excess CIF value of imports effected subsequently. The export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.”

8. Following amendments are made in **Para 2.20**-

a. In S.No. 2 the following words are added after the words Manufacturer Exporter-

“ (Except Proprietorship and Partnership firms)”

b. In the third sub-paragraph below S No. 8, the first sentence is amended to read as under-
“In respect of categories 3, 4 & 5 above, if the exporter has not exported for all the 3 preceding years, 25% Bank Guarantee condition shall be imposed on the duty saved amount, provided the CIF value does not exceed 200% of the domestic turnover or 200% of FOB/FOR value of supplies of the preceding licensing year, whichever is higher.”

9. **Para 4.7** is amended to read as under-

“The licensing authority may also issue Advance licences, where SION are not fixed, based on self declaration and an undertaking by the applicant for a final adjustment as per Adhoc/SION fixed by ALC. However, no Advance Licence for import of horn, hoof and other organ of animal, or for any item for which DGFT may so notify, shall be issued under Paragraph 4.7 by the licensing authority. For export of perfumes, perfumery compounds and various feed ingredients containing vitamins, no licence shall be issued under Para 4.7 by the licensing authority and the applicants may apply under Para 4.4.2 of handbook of Procedures, Vol-I. Where export and/or import of biotechnology items are involved, licence under Para 4.7 shall be issued by the licensing authority only on submission of a ‘No Objection Certificate’ from the Department of Biotechnology.”

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade